

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj.)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE





योजना और विकास  
के  
दस वर्ष  
राजस्थान

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय  
राजस्थान, जयपुर



इतना ही नहीं, भूमि मुबार में विस्थापित जागीरदारों को कार्य पर लगान के लिये राज्य सरकार ने योजनाएँ कियावित की हैं। जाबड़ा बोलना से विचित होने वाले क्षेत्र में इन लोगों को रिवायती बरी पर खेती करने के लिये भूमि दी गई है। राजस्थान नहर के क्षेत्र में जो रिवायती बरों पर भूमि थी जायेगी। विस्थापित जागीरदारों से जमीन की कीमत दिया गया है और आसान किशतों में वसूल की जायेगी। बन्दू खेती के भीचार खरीदने, कुएं बनवाने और रहने के लिये बसान बनवाने के लिये आसान शर्तों पर तकदी देने का भी बन्दोबस्त किया गया है।

पहली योजना में राजस्थान के लिये राखसीय योजनाओं और कैल द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय के लिये ६४.५० करोड़ रुपये की बन राशि निर्धारित की गई थी। दूसरी योजना में इन सबके लिये ११२.९० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के लिये १५ करोड़ रुपये इवीकार किये गए। पहली योजना में ५४ १४ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १२३ ७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सिंचाई की सुविधाएँ, कई छोटे, मध्यम और बड़े सिंचाई के कार्य संपादित करके बढ़ा दी गई हैं। कमलकाय जहाँ पहले १९५१-५२ में १४.८८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी वहाँ सन् १९५५-५६ में ११ ३५ लाख एकड़ में और सन् १९५८-५९ में ३५.७१ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी। खेती का एकता भी इस अवधि में बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में यह २८१ ०३ लाख एकड़ था जो बढ़ कर सन् १९५८-५९ में ३११ ०४ लाख एकड़ हो गया। भूमि मुबार, सिंचाई और खेती के उन्नत तरीके अपनाने के उद्देश्यसे राजस्थान जो कुछ काल पहले तक "जनाब सेव" था, अब न केवल खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि खाद्यान्न का निर्यात भी करने लगा है। राजस्थान में खाद्यान्न के उत्पादन के आकड़ों के जन्मजम से ज्ञात होता है कि उत्पादन वर्षों की अनिश्चितता के कारण प्रतिवर्ष बहुत अधिक बढ़ता और घटता रहता है। सही तो यह होगा कि चार साल के उत्पादन के औसतों का अध्ययन किया जाय। सन् १९५२-५६ के काल में जल का औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन था। १९५७-६१ काल का औसत ४५.५२ लाख टन जाता है। राजस्थान में जाबड़ा, जम्वाल और राजस्थान नहर से पानी मिलने पर जाभाही बरों में बंधावार और



भी दहेंगी और तब राजस्थान न केवल देश की ही बल्कि समस्या को सुलझाने में ही योग दे सकेगा वरन् राज्य में चलने वाले उद्योग धर्मों में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी पैदा कर सकेगा। राजस्थान नहर देश की शान होगी। यह दुनिया में अपने किसम की सबसे लम्बी नहर होगी। हरिके से रामगढ़ तक मुख्य नहर की लम्बाई ४२५ मील होगी। इस नहर से कुल ८० लाख एकड़ भूमि को जल होगा जिसमें से ६७ लाख एकड़ में खेती हो सकेगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का बड़ा महत्व है अतः पशुधन को विकसित करने की दिशा में विशेष रुचि देना पड़ेगी। पशु विकसितारकों की संख्या को सन् १९५०-५१ में ५७ की बढ़ कर १९६०-६१ में १०७ हो गई। इसी काब में जीवशास्त्रियों की संख्या ८८ से १४८ हुई और चलिता जीवशास्त्रियों की संख्या ३ के बढ़ कर १३ हो गई।

३१ मार्च सन् १९६१ को राजस्थान में १६० सामुदायिक विकास खण्ड थे और पञ्जाबी राज्य व्यवस्था द्वारा राजस्थान में आये थे। सामुदायिक विकास खण्ड संयुक्त राज्य में जनवरी, १९६३ तक बन जायेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में भाषातीत उन्नति हुई है। अभी हाक की अवगणना के अनुसार यहाँ अब १४.६६ प्रतिशत जनता शिक्षित है जब कि सन् १९५१ में ८.९५ प्रतिशत ही थी। कुछ क्षेत्रों में विकास का स्तर, अक्सर भारतीय औसतों के मुकाबले में कम हो सकता है, किन्तु यह सही मानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति असाह्यनीय है। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की उम्र के १४.८ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष की आयु के ५ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष की आयु के १.७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे, सन् १९६०-६१ में यह अनुपात क्रमशः ४५.७, १३.९ और ७.३ प्रतिशत हो गया। लड़कियों के लिये शिक्षा एम. ए. तक निःशुल्क है। दो विद्यार्थी बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा भी नहीं परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने हैं और जिनके अभिभावकों की आयवर्षी २५० रु० माह से कम है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना बना कर दी गई है। योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर बहुत सारी और भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। योग्य विद्यार्थियों को देश की एकड़ी से एकड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये एक छात्रवृत्ति कमिशन बनाने की योजना



राज्य सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहित करने की ओजस्वी नीति के कारण एवं बहुत सी जमीन, जल, विद्युत् आदि की सुविधाएँ और बिक्री कर और धुँगों की रिबायने देने की घोषणा के कारण बहुत से उद्योगपतियों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाने के लिये सन् १९५७ से इण्डस्ट्रीज (इक्विपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ५१ नए कारखानों के लिये लाइसेंस विमो जा चुके हैं जिनमें से नीचे लिखे हुए कुछ उल्लेखनीय हैं:—

- (१) फर्टीलाइजर फॅक्ट्री, हनुमानगढ़ (Fertilizer factory, Hanumangarh)
- (२) जिंक स्मेल्टर प्लाण्ट, उदयपुर (Zinc Smelter Plant, Udaipur)
- (३) नाईलोन फॅक्ट्री, कोटा (Nylon factory, Kota)
- (४) कैल्शियम कारबाइड, पी. वी. सी. और कास्टिक सोडा प्लाण्ट, कोटा (The Calcium Carbide, P V.C. and Caustic Soda Plant at Kota)
- (५) रेयन टायर कार्ड प्लाण्ट, कोटा (The Rayon Tyre Cord Plant at Kota)
- (६) सीमेन्ट फॅक्ट्री, चित्तौड़गढ़ (The Cement Factory, Chittorgarh)

आज के कारखाने से सन् १९६५ तक उत्पादन होने की सम्भावना है। यस्ते का कारखाना भी सन् १९६४ तक चालू हो जावेगा। नाईलोन की फॅक्ट्री बन चुकी है जिसमें जगभग मार्च १९६२ तक पूरे तौर से कार्य प्रारम्भ हो जाने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त तीन गई मिलें किशनगढ़, भीरवावा, एवं भवानोबन्दी में बन रही हैं। इसके अतिरिक्त एक टैक्सटाईल मिल के विजयनगर में खोलने के लिये भी हाल में ही भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है।



कुछ मात्र बड़ी मिलें जिनके धिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं, आधामी हो या तीन चारों में बाँट ली जायेंगी, धनका ध्येय निम्नलिखित है:—

- (१) दि साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल इन्स्ट्रुमेण्ट्स फैक्ट्री, अजमेर  
(The Scientific and Surgical Instruments  
Factory at Ajmer)
- (२) वूलन मिल्स, जयपुर एवं जोधपुर  
(Woollen Mills at Jaipur and Jodhpur)
- (३) ओक्सीजन एण्ड एसीटिलीन गैसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट, जयपुर  
(Oxygen and Acetylene Gases Manufactu-  
ring Plant at Jaipur)
- (४) वूल टोप्स एण्ड वूलन फेल्स फैक्ट्री, कोटा  
(Wool Tops and Woollen Felts Factory at  
Kota)
- (५) एक्सट्रूजन प्रेस, कोटा  
(Extrusion Press at Kota)
- (६) चिप बोर्ड प्लाण्ट, बान्सवाड़ा  
(Chip Board Plant at Banswara)
- (७) स्ट्रा बोर्ड प्लाण्ट, कोटा  
(Straw Board Plant at Kota)
- (८) फ्रैक्शनल एच. पी. मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, धोल्पुर  
Fractional H. P. Motors Manufacturing  
Industry at Dholpur)
- (९) इलेक्ट्रिकल पोर्सलैन्स इन्सुलेटर प्लाण्ट, जयपुर और कोटा  
(Electrical Porcelain Insulator Plant at Jai-  
pur and Kota)



(१०) इलेक्ट्रिकल केबल फैक्ट्री, कोटा (Electrical Cable Factories at Kota)

(११) पेपर मिल, जयपुर (Paper Mill at Jaipur)

(१२) ग्लास वूल एण्ड ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर (Glass Wool and Glass fibre factory at Jaipur)

(१३) रोलर फ्लोर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर (Roller Flour mills at Jodhpur, Pali and Udaipur)

उदयपुर में एक कीड़े मारने की दवा बनाने का कारखाना चालू किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त, मेसर्स इन्फ्रीमिटरिय इन्डस्ट्रीज, जयपुर; मान इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, जयपुर और जयपुर मेसर्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स आदि चालू कारखानों को नई वस्तुएं बनाने के लिये, उत्पादन क्षति बढ़ाने के लिये लाईसेंस दिये गये हैं । इन कारखानों में रोलर गियरिंग एक्सिस बॉलसेज, साइकिलों के छर्रे, हाई टेन्शन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन वायरस और ए. सी. एस. गार. और एल्यूमिनियम के कंडक्टर आदि नई वस्तुएं बनेंगी ।

सांकेतिक क्षेत्र में भारत सरकार ने अक्स की सहायता से एक प्रेसिजन इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्ट्री (Precision Instruments factory) कोटा में खोलने का निश्चय किया है । एक तांबा पिघलाने का कारखाना भी सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी में खोला जा रहा है । भारत सरकार डीडवाना में सोडियम-सल्फेट बनाने के लिये भी एक पायलेट प्लांट ( Pilot Plant ) लगा रही है ।

राज्य सरकार ने भी ५४ उद्योगपतियों को नए लाईसेंस देने और ३० उद्योगपतियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये लाईसेंस देने की सिफारिश कर दी है कुछ मुख्य बिन्दु के नाम, जिनके लिये सिफारिश की गई है, इस प्रकार है :

(१) पिग आयरन प्लांट, उदयपुर (Pig Iron Plant at Udaipur)



- (२) सीमेण्ट फैक्ट्री, नीमकाथाना (Cement factory at Neema-  
ka-thana)
- (३) स्कूटर/मोपेड्स फैक्ट्री, जोधपुर (Scooters/Mopeds  
factory at Jodhpur)
- (४) ऑटो मोबाइल्स टायर्स एंड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा (Automo-  
biles Tyres and Tubes Factory at Kota)
- (५) साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा और जयपुर (Cycle  
Tyres and Tubes Factories at Kota and  
Jaipur)
- (६) ब्लीचिंग डाइंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट और कॉटन  
टैक्सटाइल्स, कोटा (Bleaching, Dyeing, Finishing,  
Printing and Processing plant for cotton  
Textiles at Kota)
- (७) फ्लेक्सिबल ट्यूब्स, प्रेसिजन रिबेट्स आईर्नकास्टिंग्स मैन्युफैक्चरिंग  
फैक्ट्री, जयपुर (Flexible Tubes, Precision rivets  
Die castings, etc., Manufacturing factory at  
Jaipur)
- (८) विभिन्न स्थानों पर दस कॉटन स्पिनिंग मिलें । (Ten new  
Cotton Spinning Mills at different places)
- (९) एच. टी. एंड एल. टी. प्रोसेसिंग इन्सुलेटर फैक्ट्री, कोटा  
(H. T. & L.T. Porcelain Insulators factory  
at Kota)
- (१०) जिप्सम वाल बोर्ड्स, जिप्सम वाल प्लास्टर मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री,  
बीकानेर  
(Gypsum Wall Boards, Gypsum Wall Plasters,  
etc., Manufacturing Industry at Bikaner)



- (११) माइका कैपेसिटर्स एण्ड पेपर कैपेसिटर्स इण्डस्ट्री, जयपुर  
(Mica Capacitors and Paper Capacitors Industry at Jaipur)
- (१२) टैक्सी मीटर्स एण्ड स्पेयर पार्ट्स फॅक्ट्री, जयपुर  
(Taxi Meters and Spare Parts Factory at Jaipur)
- (१३) ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स इण्डस्ट्री, कोटा  
(Transporting Equipments Industry at Kota)
- (१४) पेपर एण्ड बोर्ड्स फॅक्ट्री, भीलवाड़ा  
(Paper and Boards Factory at Bhilwara)
- (१५) स्टील कास्टिंग्स इण्डस्ट्री, भरतपुर  
(Steel Castings Industry at Bharatpur)
- (१६) ग्रे सी. आई. कास्टिंग्स, सी. आई. एल्लोय्स आदि, रामगंज मण्डी  
(Grey C.I. Castings, C.I. Alloys etc. at Ramganj Mandi)
- (१७) स्टिफ्टाइट पोर्सलिन पार्ट्स, टेक्स्टाइल सिरेमिक्स, पी. एण्ड टी. इन्सुलेटर्स आदि, कोटा  
(Stentite Porcelain parts, Textile Ceramics, P. & T. Insulators etc. at Kota)
- (१८) लैमिनेटेड प्लास्टिक्स एण्ड फॉर्मिका शीट्स इण्डस्ट्री, कोटा  
(Laminated Plastics and Formica Sheets Industry at Kota)



(१९) रोडेंटिसाईड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोटा  
(Rodenticide manufacturing unit at Kota)  
ओर

(२०) हाउस सर्विस इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जयपुर  
(House Service Electricity Motors at Jai-  
pur)

इन्वर लिमिटेड हुई वष नई सूरी मिलों के खोलने की ओर कुछ चालू टेक्स-  
टाइल मिलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये स्वीकृति निम्न भविष्य में ही  
होने की संभावना है

निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार उन उद्योगपतियों को जो कि नए कारखाने  
खोल कर राज्य की मदद करना चाहते हैं, तब प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी।  
राज्य सरकार उन्हें उचित दरों पर पर्याप्त बिजली देने की सुविधाएँ, जमीन  
दिलाने की सहूलियतें, एवं बिजली-कर और चूनी-कर आदि में छूट देने का भरसक  
प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र को इस विषय में अधिक से  
सहयोग देने का प्रयास दिलाती है।

खनिज उत्पादन जो १९५२ में ३०४ लाख टन का हुआ,  
बढ़ कर १९५९ में ४६२ लाख टन का हो गया।  
पलाना (बीकानेर जिला) में सिमनाइड, और सोड़ी की पाल  
(झुंझपुर जिला) में एजोराइड का खनिज कार्य हाथ में ले लिया गया है।  
जुआवर खान पर एक जस्ता पिघलाने की मशीन लगा दी गई है और सोतड़ी में  
तांबा पिघलाने की मशीन लगाने की योजना है।

राज्यपान में प्रथम योजना के अन्त में कुल राज्य की आय ४०८ करोड़ ६०  
लाखी गई। १९६० के अन्त तक यह बढ़ कर, १९५४-५५ के भावों पर, ४६१  
करोड़ ६० हो गई, अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ३.३ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जब कि  
इसी काल में अखिल भारतीय औद्योगिक बढ़ोतरी ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में  
प्रति व्यक्ति आय १९५५-५६ में २३७ टन थी जो बढ़ कर १९५४-५५ के भावों



पर १९५९-६० में २४६ ब० हो गई। १९६०-६१ के मावों के आधार पर प्रति व्यक्ति खाददानी १९५९-६० के शब्द में ३१५ क० जांकी गई है।

रोजगारी संबंधी अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि द्वितीय योजना काल में राजस्थान में ३.७७ लाख अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार दिलाया गया।

विभिन्न विकास कार्यों की शुद्धाह क्य से चलाने के लिये यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित कर्मचारी उचित संख्या में प्राप्त होते रहे। राज्य सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान शक्ति संबंधी अध्ययन किये हैं। जब इनके आधार पर कार्य किया जायगा ताकि योजना को क्रियाश्रित करने में सही किस्म के कर्मचारी उचित संख्या में ब मिलने के कारण कोई बाधा उपस्थित न हो। राज्य सरकार ने राज्य सेवाओं के लिये ट्रेनिंग प्रोग्राम से सम्बंधित बातों पर विचार करने के लिये एक कमेटी बंटाई थी। इस कमेटी को सिकारियों के आधार पर ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं। तकनीकी अधिकारियों को विदेशों में विज्ञान अध्ययन के लिये भेजने की एक विनिष्ट योजना है। इस सन्दर्भ में राज्य विभिन्न विदेशों सहायता योजनाओं द्वारा मिलने वाली सहायता का भी लाभ उठा रहा है।

इस प्रकार योजना के अन्तर्गत इस वर्ष राजस्थान में राज्य की उन्नति और समृद्धि के मार्ग में निर्माणकारी युग रहा। योजना के आने वाले इस वर्षों में हमें भाषिक और सामाजिक उन्नति के लिये उच्चस्तरीय पर उत्तरोत्तर बढ़ते हुए धार सहन करने होंगे। राजस्थान के तेजी से विकास करने के लिये यह स्थिति स्वाभाविक ही है और हमें इसका बहानुरी से सामना करना पड़ेगा। अब तक किये गये, व भविष्य में किये जाने वाले प्रयास चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्षों में व उसके बाद आने वाले वर्षों में ही हमारे राज्य की जनता के रहन सहन के स्तर व समृद्धि में तेज गति से अग्रत डाल सकेंगे। भासड़ा, चम्बल, राजस्थान नहर व बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं द्वारा प्राप्त सिंचाई के कारण राजस्थान में समृद्धिवाली कृषि के लिये बहुत उन्नतवर्त भविष्य है। लघु सिंचाई के रूढ़ कार्यकर्त्ता द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। भासड़ा नांगल व चम्बल की पहली और दूसरी स्टेज की समाप्ति पर राज्य में औद्योगिक और कृषि सम्बंधी विकास के लिये



असाहसपूर्ण कार्य करने का अवसर प्राप्त होय । परन्तु फलदा सम्बंधी योजनाओं द्वारा गांधी के मायिक विकास में संतुलन प्राप्त हो सकेगा । वंचावर्ती राज्य की प्रगति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जल्द ही सामाजिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिये स्वयं अधिक से अधिक विनियोगों बहुत करनी चाहिये ।

प्राचीन नींव ढाल दी गई है और अब हम विकास और साक्षात् से सम्बन्धित और समृद्धिवादी नीति को लागू कर सकते हैं ।



इतना ही नहीं, भूमि सुधार के विस्तारित जालीरदारों को कार्य पर लाने के लिये राज्य सरकार ने योजनाएँ क्रियान्वित की हैं। बाघड़ा योजना से तिष्ठित होने वाले क्षेत्र में इन लोगों को रिवायती ढर्रे पर खेती करने के लिये भूमि दी गई है। राजस्थान नहर के क्षेत्र में जो रिवायती ढर्रे पर भूमि दी जायेगी। विस्थापित जालीरदारों से जमोन की कीमत का व्यापक के और भासान किस्मों में घटाने की जायेगी। उन्हें खेती के औजार खरीदने, हुए बनवाने और रहने के लिये नकान बनवाने के लिये आसान शर्तों पर तकदी देने का भी बन्दोबस्त किया गया है।

पहली योजना में राजस्थान के लिये रासनीय योजनाओं और क्षेत्र द्वारा संचालित योजनाओं पर व्यय के लिये ६४.५० करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी। दूसरी योजना में इन सबके लिये ११२९० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त राजस्थान नहर के लिये १५ करोड़ रुपये स्वीकार किये गए। पहली योजना में ५४.१४ करोड़ रुपये और दूसरी योजना में १२३.७३ करोड़ रुपये व्यय किये गये।

सिंचाई की सुविधाएँ, कई छोटे, मध्यम और बड़े सिंचाई के कार्य संचालित करके बढ़ा दी गई हैं। कलकत्ता वहाँ पहले १९५१-५२ में २४८८ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होती थी वहाँ सन् १९५५-५६ में ३१.३५ लाख एकड़ में और सन् १९५८-५९ में ३५.७१ लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगी। खेती का रकबा भी इस अवधि में बढ़ा है। सन् १९५५-५६ में यह २८१०३ लाख एकड़ था जो बढ़ कर सन् १९५८-५९ में ३११.०४ लाख एकड़ हो गया। भूमि सुधार, सिंचाई और खेती के उन्नत तरीके अपनाने के अन्तर्गत राजस्थान जो कुछ काल पहले तक "जमान क्षेत्र" था, अब न केवल खाजाल में आरम्भित हो गया है बल्कि खाजाल का निर्माण भी करने लगा है। राजस्थान में खाजाल के उत्पादन के माकड़ों के अन्वयन से प्राप्त होता है कि उत्पादन वर्षों की अतिममिता के कारण प्रतिवर्ष बहुत अधिक बढ़ता और बढ़ता रहता है। सही तो यह होगा कि चार साल के उत्पादन के औसतों का अध्ययन किया जाय। सन् १९५२-५६ के काल में अन्न का औसत उत्पादन ३७.४५ लाख टन था। १९५७-५९ काल का औसत ४५.५२ लाख टन जाता है। राजस्थान में बाघड़ा, अन्वय और राजस्थान नहर से पानी मिलने पर आजादी वर्षों में बाघड़ा और



भी दहेगी और तब राजस्थान न केवल देश की ही खाद्य समस्या को सुलझाने में ही योग दे सकेगा बल्कि राज्य में चलने वाले उद्योग भवनों में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी पैदा कर सकेगा। राजस्थान नहर देश की शान होगी। यह दुनिया में अपने किसिम की सबसे सम्प्री नहर होगी। हरीके से रामगढ़ तक मुख्य नहर की लम्बाई ४२५ मील होगी। इस नहर से कुल ८० लाख एकड़ भूमि को जाम होगा जिसमें से ६७ लाख एकड़ में बोती हो सकेंगी।

राज्य की अर्थ-व्यवस्था में पशु-पालन का बड़ा महत्व है अतः पशुधन को विकसित करने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया। पशु चिकित्सालयों की संख्या को सन् १९५०-५१ में ५७ की बढ़ कर १९६०-६१ में १०७ हो गई। इसी काल में औषधालयों की संख्या ८८ से १४८ हुई और चिकित्सक औषधालयों की संख्या ३ से बढ़ कर १३ हो गई।

११ मार्च सन् १९६१ को राजस्थान में १६० सामुदायिक विकास समिति में और पंचायती राज व्यवस्था के तहत राजस्थान में जायू की। सामुदायिक विकास समिति संयुक्त राज्य में अक्टूबर, १९६३ तक बन जायेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में आशातीत उन्नति हुई है। अभी तक की जनगणना के अनुसार यहाँ अब १४.६६ प्रतिशत जनता शिक्षित है जब कि सन् १९५१ में ८.९५ प्रतिशत ही थी। कुछ क्षेत्रों में विकास का स्तर, अक्सर भारतीय औसतों के मुकाबले में कम हो सकता है, किन्तु यह सभी मानते हैं कि राजस्थान में शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति सराहनीय है। सन् १९५०-५१ में ६ से ११ वर्ष की उम्र के १४.८ प्रतिशत, ११ से १४ वर्ष की आयु के ५ प्रतिशत और १४ से १७ वर्ष की आयु के १.७ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूलों में जाते थे, सन् १९६०-६१ में यह अनुपात क्रमशः ४५.७, १३.९ और ७.३ प्रतिशत हो गया। कई क्षेत्रों के लिए शिक्षा एम. ए. तक निःशुल्क है। श्री विद्यार्थी बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा भी गई परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं और उनके अभिभावकों को आसानी २५० रु० माह से कम है उनको छात्रवृत्ति देने की योजना बानू कर दी गई है। योग्यता एवं आवश्यकता के आधार पर बहुत सारी और भी छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। योग्य विद्यार्थियों को देश की एक छोटी-छोटी मजदूरी शिक्षा प्राप्त करने के सिधे छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये एक छात्रवृत्ति समीक्षा समिति की योजना



भी सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार ने देश के अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में बढ़ते जाने वाले राजस्थानी विद्यार्थियों को और अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के उन विद्यार्थियों को जो राजस्थान में बढ़ने के लिये और राज्य सरकारें भेजें, छात्रवृत्ति देने की एक नई स्कीम भी निकाली है। यह आशा की जाती है कि अन्य राज्य भी इस प्रकार की योजनाएं लागू करेंगे। देश का भावनारात्मक एकीकरण करने की दिशा में भी यह एक सुस्पष्ट कदम होगा। प्रख्यापकों और प्रास्थापताओं की बैठक में भी यह एक सुधार किया गया है। सक्कीकी जिला में प्रति आवश्यकता समस्त कर तत्परन के साथ उन्नति की गई है। राज्य में शिक्षित और योग्य व्यक्तियों की कमी को पूरा करने के लिये इन्जीनियरिंग कालेज, मंडीकल कालेज, पोस्तेटेकनिक और औद्योगिक प्रशिक्षणकेन्द्र जैसे नये।

सन् १९५९ में ही राजस्थान में, प्रति लाख व्यक्तियों पर प्राप्त शिक्षण पुनिषाद, अन्तिम भारतीय स्तर पर १९६०-६१ में प्राप्त होने वाली मुविषाओं के समान अनुपातों से अधिक हो चुकी थी, जैसा कि निम्न तालिका से स्पष्ट होगा:—

(प्रति लाख व्यक्ति)			
	भारत (१९६०-६१)	राजस्थान (१९५९)	
१. शिक्षाालय एवं औपबालय (एकोपेविक)	२.९	३.४	
२. रेली बंगला (एकोपेविक)	३६.०	४०.९	

राज्यों के एकीकरण के समय सहकारी आन्दोलन कुछ ही स्थानों पर चल रहा था। यह आन्दोलन भारत सरकार की नीति के आधार पर धीरे-धीरे और क्षमता की स्वेच्छा से बढ़ाया गया। सहकारी संस्थाओं की संख्या सन् १९५१-५२ में ४९.०८ थी। १९५५-५६ में यह ८०७७ हो गई और १९६०-६१ में १७९७४। सन् १९५१-५२ में प्राविष जनता का १.५ प्रतिशत सहकारिता से आभाषित होता था। १९५५-५६ में ५ प्रतिशत और १९६०-६१ में यह प्रतिशत बढ़ कर १४ हो गया।



पहिले जिलों के मुख्यालय भी पक्की सड़कों से सम्बद्ध नहीं थे। योजना के इन दश वर्षों में कई नई सड़कें बनाईं और यह संगमन सभी सहस्रों मुख्यालय सड़कों से सम्बद्ध हो गए हैं। राज्य में सड़कों की सम्मति सन् १९५०-५१ में ११,९७१ मील थी और यह बढ़ कर सन् १९५५-५६ में १६,९८८ मील तथा सन् १९६०-६१ में १६,७४४ मील हो गई।

सन् १९५१ में राजस्थान में केवल ३२ बिजलीघर थे, सन् १९६० में इनकी संख्या बढ़ कर ५४ हो गई। प्रति व्यक्ति बिजली का उत्पादन सन् १९५१ में ३.६९ किलोवाट घंटे था जो बढ़ कर सन् १९६० में ५.४७ किलोवाट घंटे हो गया। योजना के आरंभ में बिजली की कुल स्थापित क्षमता ३४,९०० किलोवाट थी जो बढ़ कर द्वितीय योजना के अन्त में १,०८,९९५ किलोवाट हो गई और तृतीय योजना काल के अन्त में बढ़ कर संभवतः ३,३४,४०० किलोवाट हो जायेगी। अभी १३१ शहर व गांवों में बिजली पहुँचाई जा चुकी है और निकट भविष्य में भाखड़ा और जम्ना योजनाओं द्वारा और भी स्थानों पर बिजली पहुँचाई जायेगी।

राजस्थान में कच्चे माल और खनिज पदार्थों की कमी नहीं है। फिर भी वहाँ अब तक बिजली, वातायत के साधन और कुशल कारीगरों की कमी के कारण उद्योग की प्रगति नहीं हो पाई थी। अब अब और बिजली की सुविधाएँ बढ़ा दी गई हैं। वातायत के साधन विकसित हो चुके हैं और आर्थिक सहायता का प्रावधान किया जा चुका है। तकनीकी शिक्षा का भी धरोहर कर दिया गया है। उद्योगपतियों को राज्य की ओर से सहाय रिवायते देने का भी निश्चय कर लिया गया है। हस्तकला और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। फलतः राज्य में अब आगे तेजी से औद्योगिक प्रगति की सुबूढ़ नींव बन चुकी है। राजस्थान वित्तीय नियम, केन्द्रीय सहकारी बैंक, राजस्थान राज्य उद्योग निगम से ऋण की और हस्तकला विनय फेडरों से विनय की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। पहले खनिज के क्षेत्र में, कृषि पंजीयनियों का संपन्न एकाधिकार था, किन्तु मिनरल कमिशनर कस्त बनने के बाद से साधारण स्थिति के व्यक्ति को भी खनिज व्यवसाय में लाभ छानने का अवसर प्राप्त हो चुका है।



राज्य सरकार की उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भोजवही नीति के कारण अब बहुत छी लमीन, मल, बिजुत् आदि की सुविधाएं और बिक्री कर और चुंगी की रिबायने देन की घोषणा के कारण बहुत से उद्योगपतियों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित हुआ है । विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाने के लिये सन् १९५७ से इन्डस्ट्रीज (टक्केपमेन्ट एन्ड रेगुलेशन) एक्ट, १९५१ के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा ५१ नए कारखानों के लिये लाइसेंस दिये जा चुके हैं जिनमें से नीचे किये हुए कुछ उल्लेखनीय हैं:—

- (१) फर्टिलाइजर फ़ैक्ट्री, हनुमानगढ़ (Fertilizer factory, Hanumangarh)
- (२) जिंक स्मेल्टर प्लांट, उदयपुर (Zinc Smelter Plant, Udaipur)
- (३) नाईलोन फ़ैक्ट्री, कोटा (Nylon factory, Kota)
- (४) कैल्शियम कारबाइड, पी. वी. सी. और कास्टिक सोडा प्लांट, कोटा (The Calcium Carbide, P.V.C. and Caustic Soda Plant at Kota)
- (५) रेयन टायर कॉर्ड प्लांट, कोटा (The Rayon Tyre Cord Plant at Kota)
- (६) सीमेन्ट फ़ैक्ट्री, चित्तौड़गढ़ (The Cement Factory, Chittorgarh)

आर के कारखाने से सन् १९६५ तक उत्पादन होने की सम्भावना है । अस्ते का कारखाना भी सन् १९६४ तक आरम्भ हो जावेगा । नाईलोन की फ़ैक्ट्री बन चुकी है जिसमें लगभग मार्च १९६२ तक पूरे तौर से कार्य प्रारंभ हो जाने की सम्भावना है ।

इसके अतिरिक्त तीन बड़ी मिलें किशनगढ़, मोरपारवा, एब मन्नामोमण्डी में बन रही हैं । इसके अतिरिक्त एक टैन्सटोईल मिल के विजयनगर में खोलने के लिये भी हाल में ही भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है ।



कुछ भाग बड़ी मिलें जिनके लिये साइसेस दिये जा चुके हैं, जागामी हो या तीन एवों में चारू की जावेंगी, जिनका व्योरा निम्नलिखित है:—

- (१) बि साइंटिफिक एण्ड सर्जिकल इन्स्ट्रुमेण्ट्स फैक्ट्री, अजमेर  
(The Scientific and Surgical Instruments  
Factory at Ajmer)
- (२) वूलन मिल्स, जयपुर एवं जोधपुर  
(Woolon Mills at Jaipur and Jodhpur)
- (३) ऑक्सीजन एण्ड एसिटोलीन गैसेस मैन्युफैक्चरिंग प्लाण्ट, जयपुर  
(Oxygen and Acetylene Gases Manufactu-  
ring Plant at Jaipur)
- (४) वूल टोप्स एण्ड वूलन फेल्स फैक्ट्री, कोटा  
(Wool Tops and Woollen Felts Factory at  
Kota)
- (५) एक्सट्रूजन प्रेस, कोटा  
(Extrusion Press at Kota)
- (६) चिप बोर्ड प्लाण्ट, बान्सवाड़ा  
(Chip Board Plant at Banswara)
- (७) स्ट्रा बोर्ड प्लाण्ट, कोटा  
(Straw Board Plant at Kota)
- (८) फ्रैक्शनल एच. पी. मोटर्स मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, धौलपुर  
Fractional H P. Motors Manufacturing  
Industry at Dholpur)
- (९) इलेक्ट्रिकल पोर्सिलेन इन्सुलेटर प्लाण्ट, जयपुर और कोटा  
(Electrical Porcelain Insulator Plant at Jai-  
pur and Kota)



(१०) इलेक्ट्रिकल केबल फैक्ट्री, कोटा (Electrical Cable Factories at Kota)

(११) पेपर मिल, जयपुर (Paper Mill at Jaipur)

(१२) ग्लास वूल एब्द ग्लास फाइबर फैक्ट्री, जयपुर (Glass Wool and Glass fibre factory at Jaipur)

(१३) रोलर फ्लोर मिल्स, जोधपुर, पाली और उदयपुर (Roller Flour mills at Jodhpur, Pali and Udaipur)

उदयपुर में एक लोहे बनाने की इकाई बनाने का कारखाना चालू किया जा चुका है ।

इसके अतिरिक्त, नेशनल इन्जीनियरिंग इन्स्टीट्यूट, जयपुर, मान इन्स्टीट्यूट ऑफ कारपोरेशन, जयपुर और जयपुर मेटल एब्द इलेक्ट्रिकल आदि चालू कारखानों की नई वस्तुएं बनाने के लिये, उत्पादन क्षति बढ़ाने के लिये नार्मल दिये गये हैं । इन कारखानों में रोलर मिलिंग एक्सपर्ट्स, लाइफिंग के छारे, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावरों और ए. सी. एस. बार और एल्यूमिनियम के कस्टमर आदि नई वस्तुएं बनेंगी ।

सार्वजनिक क्षेत्र में भारत सरकार ने बस की सहायता से एक प्रेसिशन इन्स्ट्रुमेंट्स फैक्ट्री (Precision Instruments factory) कोटा में खोलने का निश्चय किया है । एक तांबा विघटन का कारखाना भी सरकारी क्षेत्र में खेतड़ी में खोला जा रहा है । भारत सरकार बीडवाना में रोडमैक-सर्फेस बनाने के लिये भी एक पायलट प्लांट ( Pilot Plant ) लगा रही है ।

राज्य सरकार ने भी ५४ उद्योगपतियों की नए लाइसेंस देने और ३० उद्योगपतियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये नार्मल देने की विचारित कर दी है कुछ मुख्य बिजों के नाम, जिनके लिये सिद्धांत की गई है, इस प्रकार है :

(१) पिग आयरन प्लांट, उदयपुर (Pig Iron Plant at Udaipur)



- (२) सीमेण्ट फैक्ट्री, नीमकाथाना (Cement factory at Neem-ka-thana)
- (३) स्कूटर/मोपेड्स फैक्ट्री, जोधपुर (Scooters/Mopeds factory at Jodhpur)
- (४) ओटो मोबाइल्स टायर्स एंड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा (Automobiles Tyres and Tubes Factory at Kota)
- (५) साइकिल टायर्स एंड ट्यूब्स फैक्ट्री, कोटा और जयपुर (Cycle Tyres and Tubes Factories at Kota and Jaipur)
- (६) ब्लोचिंग डाईंग, फिनिशिंग, प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग प्लांट कौन कांटेन टेक्स्टाइल्स, कोटा (Bleaching, Dyeing, Finishing, Printing and Processing plant for cotton Textiles at Kota)
- (७) फ्लेक्सिबल ट्यूब्स, प्रेसिजन रिब्स डाईकास्टिंग्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, जयपुर (Flexible Tubes, Precision rivets Die castings, etc., Manufacturing factory at Jaipur)
- (८) विभिन्न स्थानों पर दस कांटेन स्पिनिंग मिलें (Ten new Cotton Spinning Mills at different places)
- (९) एच. टी. एल. टी. पोर्सलिन इन्सुलेटर्स फैक्ट्री, कोटा (H. T. & L.T. Porcelain Insulators factory at Kota)
- (१०) जिप्सम वाल बोर्ड्स, जिप्सम वाल प्लास्टर मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, बीकानेर (Gypsum Wall Boards, Gypsum Wall Plasters, etc., Manufacturing Industry at Bikaner)



- (११) माइका कैपेसिटर्स एण्ड पेपर कैपेसिटर्स इण्डस्ट्री, जयपुर  
(Mica Capacitors and Paper Capacitors Industry at Jaipur)
- (१२) टैक्सी मीटर्स एण्ड स्पेयर पार्ट्स फ़ैक्ट्री, जयपुर  
(Taxi Meters and Spare Parts Factory at Jaipur)
- (१३) ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स इण्डस्ट्री, कोटा  
(Transporting Equipments Industry at Kota)
- (१४) पेपर एण्ड बोर्ड्स फ़ैक्ट्री, भीलवाड़ा  
(Paper and Boards Factory at Bhilwara)
- (१५) स्टील कास्टिंग्स इण्डस्ट्री, भरतपुर  
(Steel Castings Industry at Bharatpur)
- (१६) ग्रे सी. आई. कास्टिंग्स, सी. आई. एलॉय आदि, रामगंज मण्डी  
(Grey C.I. Castings, C.I. Alloys etc. at Ramganj Mandi)
- (१७) स्टीटोपाइट पोर्सिलेन पार्ट्स, टेक्स्टाइल सिरेमिक्स, पी. एण्ड टी. इन्सुलेटर्स आदि, कोटा  
(Steatite Porcelain parts, Textile Ceramics, P. & T. Insulators etc. at Kota)
- (१८) लेमिनेटेड प्लास्टिक्स एण्ड फ़ॉर्मिका शीट्स इण्डस्ट्री, कोटा  
(Laminated Plastics and Formica Sheets Industry at Kota)



(१९) रोडेंटसाईड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोटा  
(Rodenticide manufacturing unit at Kota)  
ओर

(२०) हाउस सर्विस इलेक्ट्रिसिटी मोटर्स, जयपुर  
(House Service Electricity Motors at Jai-  
pur)

ऊपर लिखी हुई इस नई सूची मिलों के खोलने की ओर राजा बालू टेक्स-  
टाइल मिलों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिये स्वीकृति निम्नलिखित अधिकार में ही  
होने की संभावना है

निजी क्षेत्र में भी राज्य सरकार इन उद्योगपतियों को जो कि नए कारखाने  
खोल कर राज्य की मदद करना चाहते हैं, उस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करेगी।  
राज्य सरकार उन्हें उचित दरों पर पर्याप्त बिजली देने की सुविधाएँ, जमीन  
दिलाने की सुविधाएँ, एवं बिजली-ऊर और पानी-ऊर आदि में छूट देने का भरसक  
प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार निजी क्षेत्र को इस विषय में अधिक से  
सहयोग देने का दृष्टिकोण बिलायी है।

अमित उत्पादन जो १९५२ में २०४ लाख टन का हुआ,  
बढ़ कर १९५९ में ४६२ लाख टन हो गया।  
पलागा (बीकानेर जिला) में सिमनाइट, और मांडो की पाक  
(झुंझपुर जिला) में प्लोराइट का खनिज कार्य हाथ में ले लिया गया है।  
मुआवर पान पर धक अस्ता पिघलाने की मशीन खरीदी गई है और सैलरी से  
मांडो पिघलाने की मशीन खरीदने की योजना है।

राजस्थान में प्रथम योजना के अन्त में कुल राज्य की आय ४०८ करोड़ टन  
बढ़ी गई। १९६० के अन्त तक यह बढ़ कर, १९५४-५५ के भागों पर, ४६१  
करोड़ टन हो गई, अर्थात् प्रतिवर्ष औसत ३.३ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जब कि  
इस साल में अखिल भारतीय औसत बढ़ोतरी ३.१ प्रतिशत थी। राज्य में  
प्रति व्यक्ति आय १९५५-५६ में २३७ टन थी जो बड़ कर १९५४-५५ के भागों



# पंचवर्षीय योजनाएं

कोटि रु.

250

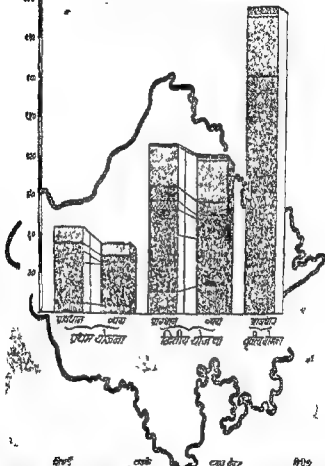
200

150

100

50

20





## योजनाएँ

२००३

जबकि देश के मध्य राज्य प्रथम पंचवर्षीय योजना के बनाने और क्रियान्वित करने में लगे हुए थे, राजस्थान स्थिर शासन व्यवस्था कायम करने, शैक्षिक-प्रोत्तरण, कानून व शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी कार्य करने में लगा हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्ष तो इन्हीं समस्याओं के मुलभूताने में धले गये, केवल योजना के तीसरे वर्ष में ही राज्य के आर्थिक विकास के लिये योजना-वद्ध कार्य प्रारम्भ किए गए। राजस्थान की प्रथम पंचवर्षीय योजना आपात योजना ( Emergency Plan ) थी।

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही हमारे राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक विकास की बिलो जूती तस्वीर सामने आई। द्वितीय योजना के दो मुख्य लक्ष्य थे—उत्पादन का बढ़ाना और रोजगारी देना। इसके अतिरिक्त, आर्थिक परिसीमा में विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं बनाना और बिजुलवार योजनाएं चलाना इस योजना के विशेष लक्ष्य थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में 'नीले के स्तर से योजना' बनाने की बिशा में वास्तविक प्रारम्भ किया गया है। पंचायत समितियों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर मुद्रपतया उ. परबोकि उन योजनाओं से सम्बन्धित थे जो कि पंचायत समितियों को स्वयान्तरित कर दी गई हैं, विभिन्न स्तरों पर बिचार किया गया और अन्त में उन्हें आर्थिक साधनों की परिमिति के अनुसार तीसरी योजना में शामिल कर लिया गया।

पहली पंचवर्षीय योजना में ६४.५० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जिसमें ३७.२१ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये थे। हाा घन राशि में से ५४.१४ करोड़ रुपये व्यय किए गए जिसमें से ३२.७४ करोड़ रुपये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर खर्च हुए। इस प्रकार, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल प्रावधान की गई राशि का ८३.९४ प्रतिशत व्यय हुआ।



दूसरी योजना में, पहली योजना में रखी गई धन राशि के दुगने से कुछ ही कम धन राशि का प्रावधान किया गया। समस्त राज्य योजनाओं के लिये १०५.९७ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं के लिये ७.३३ करोड़ रुपये की धन राशि प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त १५ करोड़ रुपये राजस्थान नहर योजना के लिये दिए गए। इन धन राशियों में से राज्य में १०२.७४ करोड़ रुपये अथवा ९७.६० प्रतिशत राज्य की योजनाओं पर और ८.७८ करोड़ रुपये अथवा ११९.७८ प्रतिशत केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर खर्च किए। १२.२१ करोड़ रुपये की धन राशि राजस्थान नहर पर खर्च की गई।

प्रथम व दूसरी योजनाओं की सकलताओं से प्रोत्साहित होकर तीसरी योजना में खर्च की जाने वाली धन राशि बहुत ही अधिक हो गई और कुल २३६.०० करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया जिसमें केन्द्र द्वारा संचालित योजनाओं पर खर्च की जाने वाली धन राशि शामिल नहीं है। इस प्रकार तीसरी योजना में खर्च की जाने वाली राशि दूसरी योजना की राशि से दुगनी से भी अधिक है। विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति तीसरी योजना में खर्च की जाने वाली राशि को देखने से पता चलता है कि जम्मू और काश्मीर को छोड़कर, राजस्थान में प्रति व्यक्ति योजना में खर्च की जाने वाली धन राशि सबसे अधिक है, जो कि १४७.५ रुपये है।

संलग्न तालिकाओं में राजस्थान सम्बन्धी सामान्य सांख्यिकीय सूचनाएँ एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रगति के निदेशक दिए गए हैं।



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



तालिका में प्रयोग किए गये संक्षेपण

+ = योजना परिचालन में नहीं।

.. = खोफड़े प्राप्त नहीं हैं।

— = कुछ नहीं।



## १.१ राजस्थान एक दृष्टि में

विषय	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. जन संख्या †	(लाख)	१५९.७	१७५.६	२०१.५
२. क्षेत्र	(हजार वर्ग मील)	१३२	१३२	१३२
३. कुल राजकीय आय	(लाख रुपये)	१५०४.५४	२६४३.२३	४५५०.८१
४. कुल राजकीय व्यय	(लाख रुपये)	१४७९.५१	२५४५.६०	४६४४.३३
५. योजना व्यय ‡	(लाख रुपये)	—	५४१४.४३	१२१७२.९७
६. साक्षरता †	(प्रतिशत)	८.९५	..	१४.६६
७. विकास लक्ष्यों के अन्तर्गत जनसंख्या	(लाखों में)	६.७५	३४.७१	९६.८६
८. पंचायत समितियाँ	(संख्या)	—	—	२३२
९. ग्राम पंचायतें	(संख्या)	२४७५	३४९०	७३९४
१०. बोया गया वास्तविक क्षेत्र प्रति व्यक्ति	(एकड़)	१.४४	१.७७	२.१३

† आंकड़े जमना: सन् १९५१ १९५६ और १९६१ के हैं।

‡ राजस्थान नहर और केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ भी शामिल हैं।



## १. सामान्य

## ११ राजस्थान एक दृष्टि में (कमला)

विषय	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
११. सिंचित क्षेत्र वास्तविक क्षेत्र एवं क्षेत्र का प्रतिफल	(प्रतिफल)	१०.८१*	११.७८	११.४८**
१२. फुल सड़के प्रति १००० वर्गमील	(मीलों में)	८९	१०६	१२७
१३. पक्की सड़के प्रति १००० वर्गमील	(मीलों में)	२७	४१	६३
१४. प्रति बसलाख व्यक्तियों पर शिक्षासाल एवं औद्योगिक	(साल)	४६	६०	९०
१५. प्रति व्यक्ति शिक्षा पर व्यय	(रुपये)	१.७३*	२.७१	६.३६††
१६. प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर व्यय	(रुपये)	०.९५*	१.९२	३.१६††
१७. प्रति व्यक्ति प्रशासन पर व्यय	(रुपये)	१.५०*	१.७०	२.१६††

आंकड़े १९५१-५२ के हैं।

\*\* आंकड़े १९५८-५९ के हैं।

†† संशोधित अनुमान।



## २.१ योजना में निर्धारित घन राशि

(लाख ₹०)

विकास का विभाग	प्रथम योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१	२	३	४
(१) राज्य योजना	२७२८.७०	१०५२७.२६	२३६००.००
(क) कृषि एवं सामुदायिक विकास	३५२.१९	१७०२.५७	३६३०.००
(ख) सिंचाई	७२२.६८	२८१३.२८	८९४५.००
(ग) विद्युत्	३६७.१०	१९९९.५१	३५००.००
(घ) उद्योग एवं सनिज	३८.५०	५७७.२१	८९५.००
(ङ) यातायात	५७२.६५	९४१.५०	१३००.००
(च) समाज सेवाएं	६७५.५८	२३९१.९०	४५९०.००
(छ) विविध	—	१०१.२९	१६०.०८
(ज) प्रजासत्तांत्रिक विकेन्द्रीकरण	—	६४.९०	५८०.००
(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएं	३७२१.५६	७३३.१९	—
(३) राजस्वार्थ बहर	—	१५००.००	६
कुल योग (१, २ और ३)	६४५०.२६	१२७६०.४५	२३६००.००

† १९५६-५७ के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं।

कुल योग में सम्मिलित नहीं हैं।

‡ प्रायधान सिंचाई के अन्तर्गत हैं।



## २. योजना

## २.२ योजना में व्यय

(लाख रु०)		
विकास का विभाग	प्रथम योजना	द्वितीय योजना
१	२	३
(१) राज्य योजना	२१४०.३८	१०२७४.१५
(क) कृषि एवं सामुदायिक विकास	२८३.८३	२२१३.२४
(ख) सिंचाई	५६३.९३	२५३०.१८
(ग) विद्युत्	१०४.६४	१५१४.९७
(घ) उद्योग एवं खनिज	३२.३३	३३८.१३
(ङ) यातायात	५१८.८१	१००७.६१
(च) समाज सेवाएँ	६३६.८४	२४३१.२१
(छ) विविध	—	११९.०३
(ज) प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण	—	११९.७८
(२) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाएँ	३२७४.०५	८७८.००
(३) राजस्थान नहर	—	१२२०.८२
कुल योग (१, २ और ३)	५४१४.४३	१२३७२.९७



## ३. कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.१ भूमि उपयोग

(हजार एकड़)

विवरण	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
१	२	३	४
१. पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल (भू- लेखानुसार)	८४७०९	८४४०६	८४३००
(क) वास्तविक बोया गया क्षेत्रफल	२३०१३ (२७.१७)	२८३०३ (३३.५४)	३११०४ (३६.९०)
(ख) पड़त भूमि	१४३९४ (१६.९९)	१४७२१ (१७.४४)	१४०९८ (१६.७२)
(ग) कृषि अयोग्य भूमि	२२१९१ (२६.२०)	१६१४३ (१९.१२)	१४९८४ (१७.७७)
(घ) अन्य जीत रहित भूमि	२२२४७ (२६.२६)	२१७५८ (२५.७८)	२१२८२ (२५.२५)
(ङ) वन	२८६४ (३.३८)	३४८१ (४.१२)	२८३२ (३.३६)
२. दुपज क्षेत्रफल	१०९२	२७०३	२८१८
३. कुल बोया हुआ क्षेत्रफल	२४१०५	३१००६	३२९२२

कोष्ठकों में दिये गए अंक पूर्ण क्षेत्रफल के प्रतिशत हैं ।



## ३. कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.२ मुख्य कृषि योजनाएँ

विवरण	इकाई	योजना काल	
		प्रथम	द्वितीय
१	२	३	४
१. नए कुएँ खोले गए	संख्या	७०५०	४१७४९
२. कुएँ गहरे किए गए	"	१७७९	२९९७१
३. तालाबों को मरम्मत की गई	"	—	५५८
४. पम्प लगाए गए	"	३४८	८६१
५. राहट लगाए गए	"	१०००	१७३२
६. जोतने योग्य बनाई गई भूमि	हजार एकड़	११	११२
७. भूमि संरक्षण	"	—	१८.८९
८. भूमि एकीकरण	वर्ग एकड़	+	१७.५२



## ३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.३ मुख्य कृषि योजनाएं (क्रमशः)

विवरण	इकाई	१९५१-५२	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. रासायनिक खाद वितरण	टन	१२४	३१३६	१२८००
२. बीज वितरण	लाख एकड़	—	१४.७०	४१.४०
३. कम्पोस्ट वितरण	लाख टन	०.१३	०.९२	१३.१४
४. हरी खाद वितरण	लाख एकड़	+	+	१.१०
५. फसलों का संरक्षण	हजार एकड़	४८५	२७९	२९.२५

\* मुख्य लाभ स्तंभों में ।



## ३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.४ मुख्य फसलें-क्षेत्रफल

(हजार एकड़)

फसलें	१९५५-५६ १९६०-६१†	
	१	२
१. सादाफ	२४६७५	२७१३७
(अ) मकाज	१७२८३	१९७६१
बाजरा	८९४८	११४१३
छापर	२८६३	२५३२
गेहूँ	२४०३	२६१२
मक्का	१३३५	१५९९
जौ	१३७२	११६६
अन्य मोटा जमाज	१९३	१९७
बाजरा	१६९	२४२
(ब) दालें	७३९२	७३७६
चना	३२३५	३३९६
सुर	३०	६२
अन्य दालें	४१२७	३९१८
२. व्यापारिक फसलें		
तिमहुन	१९८५	२०१५
गन्ना	६५	१०१

अन्तिम फोरकास्ट पर आधारित ।



## ३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.५ मुख्य फसलें—उत्पादन

(हजार टन)

फसलें	१९५५-५६	१९६०-६१*
१	२	३
१. खाद्यान्न	४१७५	४४६२
(अ) अनाज	३१२१	३२९३
बाजरा	७७७	७५२
कच्चा	२२०	२९२
गेहूँ	९०७	९८६
बरसा	५२४	५३५
जौ	५८०	५४८
अन्य मीठा अनाज	२७	३६
चावल	८६	१४
(ब) दालें	१०५४	११६९
चना	७०७	९०६
सुर	४	७
अन्य दालें	३४३	२५६
२. व्यापारिक फसलें		
तिलहन	२५२	१७०
गन्ना	४५३	९७१

\* अंतिम फीरकास्ट पर आधारित ।



## ३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.६ पशुपालन

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४
१. पशु धन (लाखों में)	२४६	३२४	..
२. विश्वविद्यालय	५७	५७	१०७
३. विस्फेग्वरी	८८	१३८	१४८
४. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	+	१	१९
५. ग्राम केन्द्र	+	६	७४
६. चर अभिधान	२	८	१३
७. सामूहिक दूध निवारण केन्द्र	+	७	७
८. गौशाला	+	१०	३०
९. गोमदन	+	२	४
१०. भेड़ व ऊँस विकास केन्द्र	+	+	६३
११. ऊँस धोनीकरण एवं बिबी केन्द्र	+	४०	७०
१२. कुक्कुट विकास केन्द्र	+	२	१६*
१३. रिप्लेक्स को रोकने के लिये इन्जेक्शन लगाने (लाखों में)	+	..	२८.५९

\* पशुचिकित्सा महाविद्यालय, बोकानेर स्थित एक कुक्कुट विकास केन्द्र भी सम्मिलित है ।



## ३.७ सहकारिता

विवरण	इकाई	१९५१-५२	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. समितियाँ	संख्या	४९०८	८०७७	१७९७४
सहकारी कृषि				
समितियाँ	"	४३	९९	६६५
बित्री समितियाँ	"	+	२	१०५
सेवा समितियाँ	"	+	+	३९४७
साख समितियाँ	"	२५६९	५१०१	७०१३
अन्य समितियाँ	"	२२९६	२८७५	६२४४
२. कुल सब्सि	"	१९८५६७	२७४७१८	८९३९३१
३. कार्यालय पंजी	लाख रु०	३४५.०५	६३५.७८	२६६७.११*
४. कुल हिस्सापूजी	"	५१.९०	९८.४४	४७१.८५*
५. ऋण विया गया	"	१९४८१	३३६.९१	१७९४.५४*
६. ऋण दत्तलो	"	१८५७२	२५५.०६	११५२.१९*
७. भुगतान तिथि पर				
बकाया ऋण	"	११.७२	५३.०३	१८०.६४*
८. केन्द्रीय सहकारी बैंक	संख्या	१२	१२	२८
९. प्रारंभिक भूमि				
वर्धक बैंक	"	२२	२२	४५
१०. बेयर हाउस	"	१	१	३२
११. गैर सरकारी व्यक्ति				
प्रशिक्षित कर्म	"	१	१	७०४३३†
१२. सहकारिता की				
परिधि में आने				
ग्राम	प्रतिशत	५	१६	५३
१३. सहकारिता की				
परिधि में ग्रामीण				
जन संख्या	"	१.५	५	२४

\* आंकड़े ३१ मार्च १९६१ के हैं।

† आंकड़े १९५९-६० वर्ष के हैं।

वर्ष १९६०-६१ के अन्त तक।



## ३ कृषि एवं सामुदायिक विकास

## ३.८ सामुदायिक विकास

विवरण	इकाई	१९५२-५३	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. खण्ड				
(अ) प्रथम स्टेज	संख्या	—	—	८४
(ख) द्वितीय स्टेज	"	—	—	५४
(स) सामुदायिक विकास*	"	८	१९	१
(द) राष्ट्रीय विस्तार सेवा*	"	—	३१	—
(न) पूर्व विस्तार	"	—	—	२१
२. विकास राज्यों के अन्तर्गत—				
(अ) (१) क्षेत्रफल	वर्गमील	४६६७	२५७०३	८३७७५
(२) राज्य के कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत	प्रतिशत	३.५४	१९.४८	३५.७७
(ब) (१) ग्राम संख्या	संख्या	१७९८	८६५५	२३६९०
(२) राज्य के कुल ग्रामों का क्षेत्रफल का प्रतिशत	प्रतिशत	५.२२	२५.१४	६८.८१
(स) (१) ग्रामीण जनसंख्या	जन संख्या	६.७५	३४.७१	१६.८६
(२) राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत	प्रतिशत	५.१९	२६.५१	७४.४२
३. जन सहयोग	लाख रु०	४.८५	१३१.३४	५४८.६४

\*पुराने स्कीम



## ४.१ बृहत् सिचाई योजनाएँ

विवरण	इकाई	राजस्थान नहर	भाखड़ा नहर (राजस्थान भाग के लिये)	घग्गल नहर* (राजस्थान भाग के लिये)
१	२	३	४	५
१. नहर क्षेत्र				
(अ) कुल लाभ- नियत क्षेत्रफल	लाख एकड़	८०	१२	१२
(ब) कृषि योग्य लाभान्वित क्षेत्रफल	"	७०	१.२०	१.१२
(स) क्षेत्रफल जिसमें सिचाई होगी	"	३६.२९	५.७०	५.५०
(द) द्वितीय योजना के अन्त तक सिचाई	"	—	२.१७	०.३७
२. नहर				
(अ) मुख्य नहर की सम्बाई	मील	४२५	५१	८२
(ब) शाखाओं प्रशाखाओं की कुल सम्बाई	"	५०००	८५०	१४००
(स) अधिकतम गहराई	फीट	..	१६	१०.५
(द) अधिकतम चौड़ाई	"	..	१०	३११
३. वित्तीय लागत				
(अ) कुल लागत	लाख ₹०	२१२८९.५४	२३८५.१६	१६४८.०८
(ब) द्वितीय योजना के अन्त तक व्यय	"	१२२०.८२	६५८.५४	१११३.७७
(स) तृतीय योजना में प्रस्तावित धन राशि	"	६३००.००	६५.००	३८८.००

\*राजस्थान सरकार द्वारा को छोड़कर



## ४ सिचाई

## ४.२ योजना के अन्तर्गत सिचाई कार्य

(हजार रुकड़)

विवरण	अनुमानित लागत लाख रु०	वित्तित क्षेत्र		
		समाप्त पर	अवधि	
			१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. महुजहलीव				
परिपोषणाएँ—				
(ग) मासुड़ा	२३८५.१६	५७०.००	१४७.००	२१७.२९
(आ) चम्बल	१९८८.०८	७००.००	—	३७.१८
२. बड़ी एवं अग्र				
मध्यम योजनाएँ				
	२८९९.००	७३९.२८	५६.००	१०६.९८
३. लघु सिचाई				
योजनाएँ				
	२७६.३०	३३०.००	५६.००	१४५.९७
४. अभाव क्षेत्र योजनाएँ				
	४८०.९८	१८९.७२	—	५२.३६
योग	७९५९.५२	२५२३.००	२५९.००	५५९.४८



## ४. सिचाई

## ४.३ सिचाई-कचलें एवं सावनवार

(हजार एकड़)

विवरण	सिंचित क्षेत्रफल		
	१९५१-५२	१९५५-५६	१९५८-५९
१	२	३	४
१. कुल सिचाई-कचलेंवार	२८९३	३९३७	४०६७
(अ) खाद्यान्न	२२५५	२९८४	३२०९
(ब) गन्ना	६२	६०	४६
(स) कपास	२४३	३०१	३५६
(द) अन्य	३३३	५९२	४५६
२. वास्तविक सिचाई-सावनवार	२४८८	३३३५	३५७१
(अ) महुएँ	५५४	७०२	८१८
(ब) तालाब	२०३	४४०	७७४
(स) कुएँ	१६८९	२१५४	१९४४
(द) अन्य साधन	४२	३२	३५
३. पुराने अधिक बार सिंचित क्षेत्रफल	४०५	६०२	४९६



## ५. विद्युत्

## ५.१ विद्युत्

विवरण	इकाई	१९५१	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
१. बिजलीघर				
(अ) डोजल	संख्या	२७	३०	४७
(ब) स्टोम	संख्या	५	५	७
२. लगे हुए कार- खानों की क्षमता*	किलोवाट में	१०२७१	३४९००	१०८९९२
३. कारबो और पाबो में बिजली पहुँचाई गई†	संख्या	४९	६६	१२१
४. दूरसमीक्षण एवं सब-दूरसमीक्षण लाइनें †				
(अ) १३२ किलो- वाट लाइनें	मील	—	—	२०२
(ब) ६६ " "	"	—	—	१४५
(स) ३३ " "	"	८५	८५	४८८
(द) ११ " "	"	१२०	१२०	२५२
(ई) ११ किलोवाट से ३३ किलोवाट में परिवर्तन	"	—	—	८४
(फ) एल. टी. लाइन से ११ किलोवाट में परिवर्तन	"	—	—	५०
५. उत्पादित बिजली	हज़ार लाख किलोवाट घंटे	५७.३९	७०.०८	११०.१७
६. प्रति व्यक्ति उत्पादित बिजली	किलोवाट घंटे	३.९९	३.९९	५.४७
७. ग्रामीणों की गई कुल बिजली	हज़ार लाख किलोवाट घंटे	४१.२२	४९.८९	८९.८४

\* केवल राजकीय विद्युत् गृहों से प्रदानित ।

† आनन्द गमक: १९५०-५१, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं ।



## ६.१ औद्योगिक योजनाएं

विवरण	इकाई	१९५४-५६	१९५६-६०
१	२	३	४
<b>१. सरकारी सहायता</b>			
(अ) खादी एवं ग्राम उद्योगों को			
ऋण	लाख रु०	४८४०	२८३.०८
सहायता	"	२.२०	८९.४४
(ब) गृह एवं लघु उद्योगों को			
ऋण	"	७८३	८९.१६]
सामाजिक व्ययित	संख्या;	१६६	२१९०
(स) बड़े उद्योगों को			
ऋण स्वीकृत किया	लाख रु०]	+	८९.८२
ऋण दिया गया	"	+	५६.४५
<b>२. हाथ करवा</b>			
बिक्री घर	संख्या	+	४८*
रंगले गृह	"	+	१९*
निरीक्ष्य एवं स्टाम्पिंग गृह	"	+	१४*
सक्ति प्राप्त करके वितरण			
किए	"	+	३००*
३. औद्योगिक वस्तियां	"	+	१४३
४. औद्योगिक न. उद्योग	"	+	५*

\* आकड़े वर्ष १९६०-६१ के हैं।

१. वे पुनः हो चके हैं और अन्य पर कार्य प्रगति पर है।



६. उद्योग एवं खनिज

६.२ औद्योगिक उत्पादन

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५

१. पंजीकृत कारखाने	संख्या	२४०	३६५	८५६
--------------------	--------	-----	-----	-----

२. मुख्य पंजी-  
कृत कारखाने

(क) कपड़ा	संख्या	१२	१३	१८
(ख) सीमेंट	"	२	२	२
(ग) शक्कर	"	३	३	६
(घ) कांच	"	१	१	१

३. उत्पादन

(क) लाठी*	आठ वर्ग मील	९.८९	२७.२१	४७.८५
(ख) कपड़ा	स स पीड	१९८.३	१८७.८	१३९.४
(ग) सूत	"	३१८.५	३७७.९	३०८.४
(घ) सीमेंट	लाख टन	२.७	५.१	९.५
(ङ) शक्कर	हजार टन	८.२	१३.६	१२.८
(च) शोशा	टन	१७०	५३५	६७२

\* आकड़े कमजोर: १९५३-५४, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं।

३ आकड़े कमजोर: १९५१-५२, १९५५-५६ एवं १९६०-६१ के हैं।



## ६. उद्योग एवं खनिज

## ६.३ खनिज उत्पादन

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९५९
१	२	३	४	५
१. समस्त खानों में रोजगार	संख्या	१३३४९	५१२८६	१०१२४२
२. समस्त उत्पा- दित खनिजों का विक्रय मूल्य	लाख रु०	३०४.५७	३६४.६५	४६२.११
३. मुख्य खनिजों का उत्पादन				
कोयला (लिफ- माइट)	हज़ार टन	४५.१३	२८.९४	२४.४३
कच्चा लोहा	"	"	५६.५५	८४.९९
मैंगनीज	"	१०.४६	२.१२	५.८३
सुरमा (कैल्सिट)	"	२.१४	३.०६	७.३३
जस्ता (स्फेटर)	"	३.८४	४.८६	१०.६४
जिप्सम	"	३३६.६८	६३३.६९	७४१.६३
अभ्रक	"	२७.५८	४९.५१	९०.८०
सोप स्टोन	"	१७.५३	३३.३८	५२.७९
चूने का पत्थर (सीमेन्ट बनाने के लिये)	"	४६७.६९	७९७.०६	१४१७.३०
चूने का पत्थर (चूना बनाने के लिये)	"	६०.८५	६१.०१	१७३.७०
आईनेशनल स्टोन	"	४८७.४	६१४.९५	२१८२.६९
इमारती पत्थर	"	१९०.००	५००.००	५५३.००



## ७. सड़क ग्रीर यातायात

## ७.१ सड़क एवं यातायात

विवरण	इकाई	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४	५
१. सड़कें	मील	११३७१	१३९८८	१६७४४
(अ) नामपुर योजना वर्गीकरण				
राष्ट्रीय राज मय	"		३७६	६२०
राजकीय राज मय	"		२३६३	२३९०
मुख्य जिला सड़कें	"	@	२४८५	२९०६
अन्य जिला सड़कें	"		५१०८	६४४३
ग्राम्य सड़कें	"		३६५६	४३८५
(ब) सतह वर्गीकरण				
सीमेन्ट की सड़कें	"	१४	४२	९४
कांकर की सड़कें	"	६२९	१९३६	४६१५
अन्य पक्की सड़कें	"	२९५७	३५०१	३६२४
कच्ची सड़कें	"	२०४१	२८००	३१९९
मोसमी सड़कें	"	५७३०	५७२९	५२८९
२. प्रति १००० वर्ग मील सड़कें	"	८६	१०६	१०७
३. प्रति १००० वर्ग मील पक्की सड़कें	"	२७	४१	६६
४. प्रति लाख जन संख्या पर सड़कों का भीतल	"	७१	८७	१०५
५. राज्य में कुल मोटर गाड़ियाँ	संख्या	९८०७	१७८३३	३२०७४

@ यह वर्गीकरण १९५४ में अपनाया गया था।

+ आकड़े सन् १९५१, १९५५, १९६० में सम्बन्धित हैं।



## ८.१ शिक्षण संस्थाएं

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विरन विद्यालय	१	१	१
२. उच्चतर माध्यमिक, तकनीकी शिक्षा बोर्ड	—	—	२
३. सामान्य शिक्षा हेतु कालेज	२७	५२	५६
४. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	८	१३	२०
५. विशेष शिक्षा हेतु कालेज	५	१७	१९
६. उच्च, उच्चतर माध्यमिक, बहुउद्देशीय विद्यालय	१७५	२७३	४५८
७. अनियत बुनियादी स्कूल	—	१४	६२
८. मिडिल स्कूल	७६२	८९३	११९४
९. अनियत बुनियादी स्कूल	+	६०५	१८०१
१०. प्रारम्भिक स्कूल	४३३६	७५८४	११२९९
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	१६	१९	५१
१२. विशेष शिक्षा हेतु स्कूल	७२६	१३८०	३३३९
योग	६०२६	१०८५१	१८३०२



## ८. समाज सेवाएं

## ८.२ निशान संस्थाओं में विद्यार्थी

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विश्व विद्यालय	२०	५९८	५५२
२. सामान्य शिक्षा हेतु कालेज	१४८४६	३११८१	३५३२७
३. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	२१२३	४३४९	५०३३
४. विशेष शिक्षा हेतु कालेज			२२१३
५. उच्चतर माध्यमिक एवं बहु-उद्देशीय विद्यालय	५९६२६	१०३३४३	७४१५०
६. हाई स्कूल			९६४७६
७. सीनियर बुनियादी स्कूल	११४४५२	१७४००६	१५६१६
८. मिडिल स्कूल			२७२८६०
९. जूनियर बुनियादी स्कूल	२२८९१६	३९६२२१	१८५९४४
१०. प्रारम्भिक स्कूल			६३४१३७
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	१२-१	१५९५	५८०३
१२. निशान शिक्षा हेतु स्कूल	२५८५८	३४३८१	७१४२८
योग	४४७११६	७४५६७४	१३९९७३९



## ८.३ शिक्षण संस्थाओं में अध्यापक

(संख्या)

विवरण	१९५०-५१	१९५५-५६	१९५९-६०
१	२	३	४
१. विश्व विद्यालय	७	१८	२९
२. सामान्य शिक्षा हेतु कालेज	५८४	१३७४	१८०१
३. व्यवसायिक शिक्षा हेतु कालेज	१४७	२३५	४८२
४. विशेष शिक्षा हेतु कालेज	८२	११७	२१५
५. उच्चतर माध्यमिक एवं बहुउद्देशीय विद्यालय	२९५२	४४६१	८२४५
६. हाई स्कूल			
७. जूनियर बुनियादी स्कूल	६२९०	८४७९	६०७
८. मिडिल स्कूल			११६६५
९. जूनियर बुनियादी स्कूल	+	१५७१	५१६३
१०. प्रारम्भिक स्कूल	७५०४	१३१७३	१९९१५
११. व्यवसायिक शिक्षा हेतु स्कूल	९४	२००	५८४
१२. विशेष शिक्षा हेतु स्कूल	२८१	५४३	६१७
योग	१७९४१	३०१७१	४९३२३



## ८. समाज सेवाएं

## ८.४ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

विवरण	इकाई	१९५२	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
<b>१. संस्थाएँ</b>				
चिकित्सालय-एलोपैथिक**	संख्या	२३४	२७५	३१२
आयुर्वेदिक	"	१३	१३	१८
श्रीवधाराय-एलोपैथिक**	"	१५८	२४७	३१०
आयुर्वेदिक	"	३३७	४८२	११४७
प्रारम्भिक स्वास्थ्य केंद्र	"	.	.	१४३१
मातृत्व एवं शिशु कल्याण केंद्र	"	३६	५१	६११
परिवार नियोजन केंद्र	"	.	७	७८१
<b>२. कार्य कर्ता</b>				
डाक्टर	"	७०२	७८५	१३३७
नर्सिंग स्टाफ @	"	१७९१	२०६०	३५८५
मिड वाइस्त	"	३२२	२४०	१००२
स्वच्छता निरीक्षक	"	९७	१११	१२६
हैल्थ विजिटर	"	२५	३२	२०६
वैक्सीनेटर	"	२९८	३२८	१९२
घंटा	"	३६२	५००	११८८
हकीम	"	१३	२०	३३

@ तिस्टर्स, मेडिटर्स, स्टाफ नर्सों एवं कम्पाउण्डरों सहित ।

आफड़े वर्ष १९६०-६१ के हैं ।

सापेक्षिक एवं निजी संस्थाओं सहित ।



## ८. समाज सेवाएं

## ८.४ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (अन्य):

विवरण	डकार्ड	१९५२	१९५५	१९६०
१	२	३	४	५
*३. क्षीमाएं	संख्या	५७७७	६३२९	८१६६
*४. रोगी निमका उपचार किया				
चिकित्सालय में भरती करके	सात	१.०४६	१.२५६	२.०४
आउट डोर में	सात	१६.८५	१३९.१६	२०६.०४
*५. प्रति दस लाख जन संख्या पर				
चिकित्सा सुविधाएं				
चिकित्सालय	संख्या	१५	१७	१७
बोधधालय	"	३१	४३	७३
डाक्टर	"	४४	४६	६७
रोगी शय्याएं	"	३६१	३७२	४०८
६. जल वितरण				
सामान्यित कस्बे	"	५	५	२७
सामान्यित जन संख्या	लाख	६.६३	६.६३	९.७२

आयुर्वेदिक सुविधाओं सहित ।

१. आयुर्वेदिक सुविधाओं के अतिरिक्त ।



## ८. समाप्त केषाएं

## ८.५ गृह निर्माण

विवरण	योग्यता काल		
	इकाई	प्रथम	द्वितीय
१	२	३	४
१. औद्योगिक अभिक गृह निर्माण योजना			
(अ) कुल व्यय	लाख रु.	२.४९	४७.४९
(आ) बनाये गये गृह	संख्या	.	११२२
२. काम-आमदनी वालों के लिये गृह निर्माण योजना			
(अ) वितरित ऋण	लाख रु.	६२.८१	१७१.२९
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	२०२	४०८१
३. माध्यमिक आमदनी वालों के लिये गृह निर्माण योजना			
(अ) वितरित ऋण	लाख रु.	+	५७.६३
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	+	१९५
४. गंदी बस्तियों का सुधार			
(अ) वितरित ऋण	लाख रु.	+	२.७३
(आ) बनाए गए गृह	संख्या	+	१२०
५. ग्रामीण गृह योजना			
(अ) वितरित रकम	लाख रु.	+	३६.६५
(आ) लाभान्वित ग्राम	संख्या	+	३००



## ८.६ धर्म एवं रोजगार

(संख्या)

विवरण	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३
१. कल्याण केन्द्र	१२	२५
अ क्षेत्री	—	१
ब क्षेत्री	—	८
स क्षेत्री	१२	८
२. रातकीय बीमा योजना		
(अ) कार्यशील केन्द्र	..	८
(ब) लाभान्वित व्यक्ति	..	१२८०००
(स) औपचारिक	..	६
३. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज	७	१८
४. लाइव रजिस्टर पर व्यक्ति	१७२३५	४०४९१
५. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा व्यक्तियों की रोजगार वितरित गया	४२२९	१९९२५
६. मजदूर संघ	१५०	३७४



## ८. सामान सेवाएं

## ८.७ सामान कल्याण एवं पिछड़ी हुई जाति कल्याण

विवरण	(संख्या)		
	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४
१. स्कूल	५२	१३०	१४०
२. छात्रावास	१०	२२	४४
३. छात्रों को दी गई छात्रवृत्तियाँ	१४८७	१७५४३	१८१६०
४. परिवारों को सहायता—			
(अ) पुनर्वास के लिए	११५	१५११	६२१
(प) सिंचाई के कुएँ बनाने के लिये	१६३१	२८०५	१०९७
(स) पानी पीने के कुएँ बनाने के लिये	+	८२	७५६
५. गृह उद्योग केन्द्र	७	३४	८४
६. शीपचालय	+	११	११
७. संस्कार केन्द्र	+	३४	५१
८. सामाजिक शिक्षा केन्द्र*	५	१९७	२३९
९. आश्रय गृह	+	+	३
१०. निला आश्रय गृह	+	+	११
११. भित्तारी गृह	+	+	२
१२. कल्याण विस्तार परियोजनाएँ	+	८	३३

\* साँकड़ें २३२ में से १५५ पंचायत समितियों से प्राप्त सूचना के आधार पर हैं।



९. विविध

६.१ प्रशिक्षण एवं शिक्षा

(संख्या)

विषय	१९५०-५१	१९५५-५६	१९६०-६१
१	२	३	४
१. छपि शिक्षा			
(क) कॉलेज	१	२	२
(आ) प्रशिक्षण केन्द्र (ग्राम सेवाएँ)	+	४	५
२. पत्र विनिर्मा कॉलेज	+	१	१
३. चिकित्सा संस्थाएँ			
(अ) मेडिकल कॉलेज	१	१	२
(आ) जायुर्वेदिक कॉलेज	१	१	२
(ई) प्रशिक्षण केन्द्र	..	..	५१
४. इंजीनियरिंग संस्थाएँ			
(क) कॉलेज	१	२	२
(ख) पोलिटैक्निक	+	१	६
५. तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र	+	२	६
६. औद्योगिक उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र	+	+	४७
७. वन प्रशिक्षण संस्थाएँ	+	४	४
८. सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र	+	१	२